केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ सड़कों पर मुख्यमंत्री भजनलाल उतरेंगे सड़कों पर

एसआईआर पर भाजपा की आर-पार की तैयारी, कांग्रेस के आरोपों का हर मोर्चे पर जवाब देगी पार्टी

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर । मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस के आरोपों और कथित दुष्प्रचार का जवाब देने के लिए भाजपा ने अब सड़क से सदन तक आर-पार की लडाई के लिए मोर्चा खोल दिया है।

पार्टी ने साफ संकेत दिए हैं कि सांसद हो या विधायक, विधानसभा हो या सड़क हर मोर्चे पर जनता के बीच जाकर कांग्रेस के आरोपों का जवाब दिया जाएगा और एसआईआर को लेकर फैलाए जा रहे कथित भ्रम को बेनकाब किया जाएगा। इसी रणनीति के तहत 5 नवंबर को जयपुर में होने वाली "लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ" पदयात्रा में केंद्रीय सूचना प्रसारण और रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे।

- **जयपुर के रामलीला मैदान की जनसभा में मुख्यमंत्री सहित जुटेंगे पार्टी के दिग्गज**

कार्यक्रम संयोजक सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि रामलीला मैदान में जनसभा के बाद भाजपा की सांकेतिक पदयात्रा चौड़ा रास्ता होते हुए त्रिपोलिया गेट तक जाएगी। रेलमंत्री वैष्णव , मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी जनसभा और पदयात्रा में शामिल होंगे। इस आयोजन के जरिए एसआईआर पर अपना पक्ष जनता तक पहुंचाने के साथ कांग्रेस के आरोपों का राजनीतिक जवाब देने की तैयारी में है। पार्टी ने कार्यक्रम में 10 हजार से अधिक लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा है।

सांसद मंजू शर्मा ने बताया कि 5 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी एसआईआर को लेकर जनता के बीच अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। भाजपा का मानना है कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा और सूची को अधिक विश्वसनीय बनाने की प्रक्रिया है।

मंजू शर्मा के अनुसार, कांग्रेस इस मुद्दे पर भ्रम पैदा कर रही है और चुनावी प्रक्रिया के प्रति अविश्वास का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा कार्यकर्ता जनता के बीच जाकर इन आरोपों का जवाब देंगे। भाजपा ने पदयात्रा का मार्ग तय करते समय दीपावली के खरीदारी सीजन और परकोटे के बाजारों की व्यावसायिक गतिविधियों को भी ध्यान में रखा है। त्योहार के दौरान बाजारों में बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही रहती है। ऐसे में लंबे मार्च से यातायात और कारोबार प्रभावित होने की आशंका थी। इसी कारण रामलीला मैदान से त्रिपोलिया गेट तक सांकेतिक पदयात्रा रखी गई है। पार्टी की कोशिश है कि राजनीतिक संदेश भी प्रभावी ढंग से पहुंचे और व्यापारियों तथा आमजन को कम से कम परेशानी हो।

इस कार्यक्रम के लिए विधानसभा क्षेत्र, मंडल और वार्ड स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई है। मंडल अध्यक्षों, पार्षदों, पार्षद प्रत्याशियों और वार्ड प्रभारियों को कार्यकर्ताओं की ज्यादा से ज्यादा संख्या जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

आई.डी.बी.आई. बैंक विदेशी कंपनी को बेचने के विरोध में धरना-प्रदर्शन

निजीकरण के विरोध में राजस्थान की सभी शाखाओं में कर्मचारियों ने हड़ताल करके विरोध जताया

जयपुर । केंद्र सरकार की ओर से आईडीबीआई बैंक को कनाडा के फेयरफैक्स समूह को बेचे जाने के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ आईडीबीआई ऑफिसर्स एंड एम्प्लाइज के आव्हान पर राजस्थान की सभी शाखाओं में दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल के तहत पूर्ण हड़ताल रही।



आईडीबीआई बैंक की जयपुर की सी-स्कीम शाखा पर कर्मचारियों ने धरना देकर विरोध जताया।

इस दौरान जयपुर के सी-स्कीम स्थित मुख्य शाखा के सामने कर्मचारियों और अधिकारियों ने धरना-प्रदर्शन कर निजीकरण के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन में जयपुर सहित प्रदेश की विभिन्न शाखाओं से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। खास बात यह रही कि महिला कर्मियों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी निभाते हुए निजीकरण को महिला और परिवार विरोधी बताया।

सभा को राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लाइज यूनियन के नेता आर.ए. शर्मा, सहकार नेता सूरज भान सिंह आमेरा, महेश शर्मा, आर.जी. शर्मा, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन (एआईबीओए) के महासचिव नरेश शर्मा, आईडीबीआई इकाई अध्यक्ष हरीश मीणा, सचिव मनोज मीणा और नीलिमा सोलंकी ने संबोधित किया। सूरज भान सिंह आमेरा ने कहा कि सरकार और एलआईसी ने 46 हजार करोड़ रुपये की पूंजी लगाकर तथा कर्मचारियों की मेहनत से आईडीबीआई बैंक को पुनर्जीवित किया है। बैंक लगातार 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक का लाभ कमा रहा है और उसका एनपीए 31.78 प्रतिशत से घटकर 2.30 प्रतिशत रह गया है। ऐसे लाभकारी बैंक को विदेशी कंपनी को बेचना जनता के साथ धोखा और बैंकिंग व्यवस्था का विदेशीकरण है। नरेश शर्मा ने कहा कि एआईबीओए, राजस्थान प्रदेश बैंक एम्प्लाइज यूनियन और सहकार आंदोलन इस संघर्ष में आईडीबीआई कर्मचारियों के साथ खड़े हैं, यह लडाई केवल आईडीबीआई की नहीं, बल्कि देश की सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था को बचाने की है।

प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से निजीकरण की प्रक्रिया तत्काल रद्द कर बैंक को सार्वजनिक क्षेत्र में बनाए रखने की मांग की। धरने में 'आईडीबीआई बैंक बचाओ, देश बचाओ', 'निजीकरण वापस लो' और 'विदेशीकरण बंद करो' के नारे लगाए गए।

कुएं में गिरी बुजुर्ग महिला को पुलिस ने बचाया

जयपुर। दौलतपुरा थाना क्षेत्र के चोंप गांव में सास-बहू के बीच विवाद के बाद एक बुजुर्ग महिला के कुएं में गिरने का मामला सामने आया है। मंगलवार सुबह सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से महिला को करीब 50 फीट गहरे सूखे कुएं से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दौलतपुरा थानाधिकारी महेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मंगलवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को चोंप गांव की अहीरों की ढाणी में एक महिला के कुएं में गिरने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस की पीसीआर वैन करीब दस मिनट में मौके पर पहुंच गई। घटनास्थल पर पता चला कि महिला घर से करीब 200 मीटर दूर स्थित बिना मुंडेर के सूखे कुएं में गिरी हुई है। पुलिस की महिला कांस्टेबल राज किरण और चालक सिपाही तेजपाल ने तत्काल बचाव कार्य शुरू किया। तेजपाल कुएं में उतरे और खाट की मदद से महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि सोमवार रात घर पर सास और बहू के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद बुजुर्ग महिला घर से चली गई। परिजन रातभर उसकी तलाश करते रहे। मंगलवार सुबह महिला के कुएं में गिरने की जानकारी मिलने पर आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य पूरा कर महिला की जान बचाई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

'लीवर स्क्रीनिंग में राजस्थान है देश में अव्वल, 3.20 करोड़ लोगों की जांच'

"मिशन लीवर स्माइल" के तहत 7 हजार से अधिक चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया

जयपुर (कासं)। राजस्थान में लीवर संबंधी बीमारियों की समय पर पहचान और रोकथाम के लिए संचालित मिशन लीवर स्माइल के तहत अब तक 3.20 करोड़ से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। इसके साथ राजस्थान देश में सर्वाधिक लीवर स्क्रीनिंग करने वाला राज्य बन गया है। मंगलवार को अभियान के तहत प्रदेश के 7 हजार से अधिक चिकित्सकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज (आईएलबीएस), नई दिल्ली के निदेशक एवं चांसलर प्रो. (डॉ.) एस.के. सरीन ने कहा कि बेहतर जीवनशैली और उपयुक्त खानपान की सलाह भी चिकित्सकीय पर्चे जितनी महत्वपूर्ण है। फैटी लीवर और फाइब्रोसिस की समय पर जांच तथा संभावित मरीजों की पहचान के लिए एएलटी टेस्ट पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है।



इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज नई दिल्ली के निदेशक एवं चांसलर प्रो. डॉ. एस.के. सरीन और प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ।

प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित प्रशिक्षण में डॉ. सरीन और उनकी विशेषज्ञ टीम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेडिकल कॉलेज से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक के चिकित्सकों एवं अधिकारियों को फैटी लीवर रोग की स्क्रीनिंग, जोखिम की पहचान, जांच और प्रबंधन की जानकारी दी।

गायत्री राठौड़ ने बताया कि दिसंबर से आयोजित होने वाले ग्रामीण स्वास्थ्य शिविरों में लीवर की जांच एवं परामर्श पर विशेष जोर दिया जाएगा। स्कूलों में भी विद्यार्थियों को स्वस्थ लीवर, बेहतर जीवनशैली, खानपान और लीवर संबंधी बीमारियों के लक्षणों के प्रति जागरूक किया जाएगा। डॉ. सरीन ने एएनएम, सीएचओ और आशा सहयोगिनियों के प्रशिक्षण के साथ शिविर लगाने तथा स्थानीय भाषाओं में जागरूकता सामग्री तैयार करने का सुझाव दिया।

जांच की तकनीक और जोखिम आंकलन का प्रशिक्षण

आईएलबीएस के डॉ. बी.बी. रेवारी और डॉ. कनिका कौशल ने राष्ट्रीय गैर-संचारी रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के तहत फैटी लीवर की स्क्रीनिंग एवं प्रबंधन की जानकारी दी।

प्रशिक्षण में कमर की माप, एफआईबी-4 स्कोरिंग तथा एलएसएम और सीएपी पैरामीटर से लीवर की स्थिति का आकलन करने की प्रक्रिया समझाई गई। इसमें मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य, अस्पताल अधीक्षक, प्रोफेसर, जोनल संयुक्त निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला एवं उप जिला अस्पतालों के पीएमओ, मिशन के नोडल अधिकारी, ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी और विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी शामिल हुए। प्रशिक्षण के बाद प्रतिभागियों को ई-प्रमाण पत्र दिए गए।

एएनएम-सीएचओ का प्रशिक्षण 4 से 6 नवंबर तक

मिशन के तहत 4 से 6 नवंबर तक एएनएम एवं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (सीएचओ) का ऑनलाइन प्रशिक्षण होगा। इसमें जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान, खानपान एवं जीवनशैली संबंधी परामर्श, स्क्रीनिंग के लिए प्रेरित करने और जरूरतमंद मरीजों को उचित स्वास्थ्य संस्थान तक भेजने की प्रक्रिया बताई जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंस में निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त निदेशक अस्पताल प्रशासन डॉ. नरोत्तम शर्मा और राज्य नोडल अधिकारी एनसीडी डॉ. सुनील सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे।

लोक लेखा समिति का दायरा बढ़ाने की जरूरत : जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने तिरुवनंतपुरम में आयोजित लोक लेखा समिति (पीएसी) के सभापतियों के सम्मेलन में समितियों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि पीएसी का दायरा केवल वित्तीय अनियमितताओं की जांच तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि सरकारी योजनाओं के प्रदर्शन, उनके परिणामों और खर्च की उपयोगिता का भी आंकलन होना चाहिए। जूली ने सुझाव दिया कि समितियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाएं और प्रत्येक माह चार विभागों के कामकाज की समीक्षा की जाए। उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी, स्वायत्त संस्थाओं और विशेष प्रयोजन संस्थाओं को भी समिति की जांच के दायरे में शामिल करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विभागों से समय पर जवाब लेना और उनकी ओर से की गई कार्रवाई रिपोर्ट का नियमित फॉलोअप जरूरी है।

सार-समाचार

नि:शुल्क चिकित्सा शिविर में 125 लाभांवित



जयपुर । राइजिंग होप्स सोसायटी और विकास समिति सेक्टर-12, मानसरोवर के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत नि:शुल्क चिकित्सा आउटरीच शिविर आयोजित किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय और शहरी सामुदायिक केंद्र सेक्टर-12, इंद्रपथ के सहयोग से आयोजित शिविर में करीब 125 महिला, पुरुष और बच्चों ने स्वास्थ्य जांच करवाई। शिविर में सीबीसी, हीमोग्लोबिन, लीवर, किडनी, शुगर, इलेक्ट्रोलाइट, विटामिन, फेरिटिन और एएनसी सहित सभी जांचें नि:शुल्क की गईं। मरीजों को चिकित्सालय की ओर से दवाइयां भी नि:शुल्क उपलब्ध कराई गई। राइजिंग होप्स सोसायटी के अध्यक्ष श्याम सुंदर सारस्वत ने बताया कि शिविर में डॉ. तरुण तिवाड़ी, ब्लॉक सीएमएचओ सहित छह चिकित्सा विशेषज्ञों ने सेवाएं दीं। इनमें डॉ. रजनी शर्मा (प्रभारी), डॉ. मीनाक्षी धाकड़ (स्त्री रोग), डॉ. जितेंद्र शर्मा (शिशु रोग), डॉ. परीक्षिता शर्मा (मेडिसिन), डॉ. निशा शर्मा (चिकित्सा अधिकारी) और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉ. विवेक मोहन गुप्ता शामिल रहे। नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारियों ने भी सहयोग किया। सर्वर बंद होने के कारण कुछ समय मरीजों को जांच के लिए इंतजार करना पड़ा। विकास समिति के अध्यक्ष सुरेश चंद जैन ने चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों का सम्मान कर आभार जताया। शिविर में आनंद प्रकाश माथुर, नितेंद्र माथुर, प्रिया ज्ञानानी, दामोदर दास माहेश्वरी, दिनेश शर्मा, डॉ. राजेंद्र प्रसाद शर्मा, डॉ. के.के. अग्रवाल, मूलचंद बसंतानी, इंदर ज्ञानानी, भगवान दास, प्रदीप सक्सेना, प्रकाश कुमार मूलवानी, शिक्षक चंद जैन, सुरेश कुमार भम्मानी और राधेश्याम उपाध्याय सहित कई लोग उपस्थित रहे।

सहकारी बैंकिंग व्यवस्था पर चर्चा



जयपुर । सहकारिता रजिस्ट्रार एवं शासन सचिव डॉ. समित शर्मा की अध्यक्षता में सहकारिता विभाग से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण, ई-पैक्स एवं एम-पैक्स के प्रभावी क्रियान्वयन तथा किसानों को सुलभ बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने निर्देश दिए कि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण के शेष कार्यों को प्राथमिकता से पूर्ण करते हुए उन्हें शीघ्र ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाए। कम्प्यूटरीकृत समितियों को गो-लाइव करने तथा उनकी कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने ई-पैक्स एवं एम-पैक्स के प्रभावी संचालन पर जोर देते हुए कहा कि कम्प्यूटरीकरण के साथ-साथ सिस्टम ऑडिट, डायनेमिक डे-एंड प्रक्रिया तथा अन्य तकनीकी गतिविधियों की नियमित निगरानी की जाए, ताकि सहकारी संस्थाओं का संचालन सुचारू रूप से हो सके। डॉ. शर्मा ने सहकारी बैंकिंग सेवाओं के विस्तार के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, किसान क्रेडिट कार्ड तथा माइक्रो एटीएम जैसी सुविधाओं के माध्यम से किसानों को गांव स्तर पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करते हुए सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में सहकारी संस्थाओं के तकनीकी सुदृढ़ीकरण, डिजिटल सेवाओं के विस्तार तथा किसानों को सहकारिता के माध्यम से बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया।

'जल संरक्षण जरूरत और जिम्मेदारी'

जयपुर। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल में 'ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह-2026' के तीसरे दिन मंगलवार को 'जल संरक्षण' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य पर्यावरण अभियंता प्रेमलाल ने कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जल संरक्षण की शपथ लेकर पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करने का संकल्प लिया। मुख्य पर्यावरण अभियंता विष्णु दत्त पुरोहित ने कहा कि जल जीवन का आधार है और इसका संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। पानी की बर्बादी रोकने और दैनिक जीवन में छोटे-छोटे उपाय अपनाने से बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने व्यक्तिगत एवं संस्थागत स्तर पर जल बचत को जीवनशैली का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। सहायक मुख्य पर्यावरण अभियंता भुवनेश माथुर ने जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की जानकारी देते हुए जल प्रदूषण की रोकथाम, अपशिष्ट जल के उपचार और जल स्त्रोतों को स्वच्छ रखने में मंडल की भूमिका बताई। वरिष्ठ पर्यावरण अभियंता विजय शर्मा ने वर्षा जल संचयन, जल के पुन: उपयोग और घरों, कार्यालयों एवं औद्योगिक इकाइयों में पानी की बर्बादी रोकने के व्यावहारिक उपाय बताए।

राजीविका दिवाली मेले में ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, बंधेज व हस्तनिर्मित उत्पादों की मांग

जयपुर (कासं)। राजीविका दिवाली मेला-2026 में खरीदारी का उत्साह चरम पर पहुंच गया है। सातवें दिन भी बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने ग्रामीण महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार हस्तनिर्मित उत्पादों, पारंपरिक हस्तशिल्प, सजावटी सामग्री और घरेलू उपयोग की वस्तुओं की जमकर खरीदारी की।

मेले में ब्लैक पॉटरी, ब्लू पॉटरी, कोटा डोरिया, मोडल सिल्क, अजरख प्रिंट और बंधेज की साड़ियों व सूट की खूब मांग रही। टेराकोटा, मीनाकारी, कशीदाकारी, हैंडमेड अगरबत्ती, जूट के बैग, पापड़-अचार और चमड़े के उत्पाद भी खरीदारों को आकर्षित कर रहे हैं। इन उत्पादों के जरिए ठाामीण महिलाओं को अपने हुनर और उद्यमशीलता के लिए बड़ा बाजार मिल रहा है।

मेले में 10 से अधिक खानपान स्टॉल्स पर भी भीड़ रही। यहां राजस्थानी थाली, बाजरे की खिचडी, मिस्सी रोटी के साथ दाबेली, भेल, फास्ट फूड और प्राकृतिक हस्तनिर्मित आइसक्रीम उपलब्ध हैं। परिवारों ने खरीदारी के साथ विभिन्न व्यंजनों का भी आनंद लिया। 28 अक्टूबर से शुरू हुए राजीविका दिवाली मेले का बुधवार, 4 नवंबर को अंतिम दिन है। मेला सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहेगा। प्रवेश नि:शुल्क है। शहरवासी अंतिम दिन ग्रामीण महिला उद्यिमयों के हस्तशिल्प, पारंपरिक कलाओं और स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर सकते हैं।



घर में चल रहा था जुए का अड्डा, चार गिरफ्तार

जयपुर। दीपावली के मद्देनजर जुआ-सट्टा और संगठित अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गलतागेट थाना पुलिस ने लुहार बस्ती में एक मकान पर दबिश देकर चार जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से 1 लाख 4 हजार 400 रुपए की दांव पर लगी राशि और ताश के 52 पत्ते बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त करण शर्मा ने बताया कि गलतागेट थानाधिकारी धर्मेंद्र शर्मा के नेतृत्व में विशेष टीम ने लुहार बस्ती स्थित एक मकान में दबिश देकर अनिल लुहार उर्फ बल्लू (27), योगेश लुहार (32), मोहम्मद उस्मान (35) और दयाल लुहार (24) को जुआ खेलते गिरफ्तार किया। अनिल, योगेश व दयाल गणेशपुरी कच्ची बस्ती, गलतागेट के निवासी हैं, जबकि मोहम्मद उस्मान करीम कॉलोनी, ईदगाह का रहने वाला है।

घर बैठे अपडेट होगा पेंशनर्स का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र

जयपुर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के समन्वय से पेंशनर्स को घर बैठे नि:शुल्क डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) अपडेट कराने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 1 से 30 नवंबर तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।



ईपीएफओ जयपुर की ओर से पेंशनर्स को पत्राचार, दूरभाष और प्रतिमाह आयोजित होने वाले 'निधि आपके निकट 2.0' शिविरों के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र समय पर अपडेट कराने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-द्वितीय (पेंशन) तुषार उत्तम जाधव और आईपीपीबी परिमंडल कार्यालय राजस्थान के वरिष्ठ प्रबंधक अशोक कुमार भुराड़िया के बीच बैठक हुई। इसमें अधिक से अधिक पेंशनर्स को इस सुविधा से जोड़ने पर चर्चा की गई। पेंशनर्स डाक सेवा के माध्यम से घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र अपडेट करवा सकेंगे। इसके लिए नजदीकी आईपीपीबी शाखा या ग्रामीण डाक सेवक से संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए मोबाइल से ऑनलाइन भी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा उपलब्ध है।

'बिना वैध अधिसूचना के दूसरे राज्यों की कारों से टैक्स नहीं वसूल सकते'

हाईकोर्ट ने दूसरे राज्यों की प्राइवेट कार-जीप के राजस्थान में 30 दिन से ज्यादा संचालन पर परिवहन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई को अवैध करार दिया

जयपुर (कासं)। राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि परिवहन विभाग बिना वैध अधिसूचना के दूसरे राज्यों की गैर परिवहन कार-जीप पर टैक्स वसूलने की कार्रवाई नहीं कर सकता। वहीं अदालत ने दूसरे राज्यों की प्राइवेट कार-जीप के राजस्थान में 30 दिन से ज्यादा संचालन पर परिवहन विभाग की ओर से की गई कार्रवाई को अवैध करार दिया है।

सीजे संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश हार्पी कोर नेटवर्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सहित करीब 90 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं से टैक्स के तौर पर वसूली गई राशि 30 दिन में परिवहन विभाग वापस करे और उनके जब्त वाहनों को भी तुरंत रिलीज करें। इस मामले में कई वाहन मालिकों की निजी कारें राजस्थान के बाहर के राज्यों में रजिस्टर्ड थी। इनमें हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों के वाहन शामिल थे। इन वाहनों का संबंधित राज्यों में रजिस्ट्रेशन था और उन पर लाइफटाइम टैक्स भी जमा किया हुआ था, लेकिन जब ये वाहन प्रदेश में चल रहे थे तो परिवहन विभाग की उड़नदस्ते टीम ने कई वाहनों को रोककर कार्रवाई की थी।

परिवहन विभाग का कहना था कि दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी वाहन राजस्थान में 30 दिन से अधिक समय तक रखे जा रहे हैं। वाहन मालिकों ने राजस्थान में निर्धारित रोड टैक्स जमा नहीं किया। इसलिए राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम-1951 के तहत इन वाहनों पर टैक्स बकाया है। दूसरी ओर वाहन मालिकों की दलील थी कि वाहन का रजिस्ट्रेशन और लाइफटाइम टैक्स दूसरे राज्य में पहले जमा है तो राजस्थान में एकमुश्त टैक्स की मांग का कोई आधार नहीं है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि 10 जुलाई 2024 की अधिसूचना में यात्री वाहनों और माल वाहनों के लिए टैक्स की दरें निर्धारित की थी। गैर-परिवहन निजी कारों के लिए संबंधित धारा में अलग अधिसूचना उपलब्ध नहीं थी। इसलिए मौजूदा अधिसूचना से दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड निजी कारों से एकमुश्त टैक्स नहीं वसूल सकते।

विद्याधर का बाग में शादी-समारोह और सभी व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल लगाओ पूर्ण प्रतिबंध : हाईकोर्ट

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आरक्षित वन क्षेत्र में स्थित विद्याधर का बाग में शादी समारोह सहित अन्य सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।

- **अदालत ने वन क्षेत्र के निकट की संपत्ति में रेस्तरां संचालन का टैंडर देने पर सवाल खड़ा करते हुए केस के प्रभारी अधिकारी को 8 दिसंबर को हाजिर होने के आदेश दिए**

अदालत ने वन क्षेत्र के निकट की संपत्ति में रेस्तरां संचालन का टेंडर देने पर सवाल खडा करते हुए केस के प्रभारी अधिकारी को 8 दिसंबर को हाजिर होने को कहा है। अदालत ने मामले में अधिवक्ता अपेक्षा बापना को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करते हुए उन्हें मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीजे संजय के अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने यह आदेश सिटीजन प्रोटेक्शन सोसायटी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि यह संपत्ति वन्यजीव क्षेत्र के ठीक बगल में है। यहां देर रात के समय आतिशबाजी और लेजर लाइट के उपयोग से वन्यजीवों को असुविधा होती है। ऐसे में इन पर प्रतिबंध लगाना उचित है। अदालत ने कहा है कि गत 29 सितंबर को आदेश जारी कर याचिका को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने को कहा गया था, लेकिन इसे फिर से एडमिशन की श्रेणी में लिस्ट किया गया है। ऐसे में हाईकोर्ट की रजिस्ट्री इस संबंध में पेश करे।

जनहित याचिका में कहा गया कि विद्याधर का बाग एक घोषित स्मारक है और रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में स्थित है। यहां शादी और निजी समारोह जैसे आयोजन किए जाते हैं। जिसके कारण देर रात तक तेज संगीत, लेजर लाइट और आतिशबाजी होती है। इसके अलावा 14 सितंबर, 2022 को टेंडर जारी कर रेस्तरां का संचालन भी किया जा रहा है। जिससे वन्यजीवों के विचरण पर प्रभाव पड रहा है। वहीं ऐसी गतिविधियां फॉरेस्ट एरिया में नहीं चल सकती है।

दूसरी ओर राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता माही यादव ने कहा कि साल 2022 में जारी टेंडर की अवधि पूर्व में ही समाप्त हो चुकी है इसके अलावा वर्तमान में यहां ऐसी कोई गतिविधि संचालित नहीं हो रही है। वन विभाग की ओर से हाजिर अधिवक्ता ने भी एएजी के बात को दोहराया। सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने यहां शादी समारोह सहित सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।